सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

वर्ष 1 अंक 4 | अप्रैल 1979 | पचास पैसे

मद्रास में सीटू सम्मेलन की पूरी तैयारी

सीटू के चौथे सम्मेलन की तैयारी कमेटी अब सीटू सम्मेलन की तैयारियों को अंतिम रूप देने में व्यस्त है. सम्मेलन की शानदार सफलता के लिए मद्रास में और उसके आस-पास और तमिलनाडु के अन्य स्थानों में कई बैठकें की गई. चंदा इकठ्ठा करने के लिए बड़े जोर-शोर से अभियान चलाया गया है, और तमिलनाडु कामरेड यह आशा करते हैं कि सम्मेलन के खर्चों को चलाने के लिए पर्याप्त धन इकठ्ठा हो जाएगा.

देश के सभी भागों से आने वाले 5,000 डेलीगेटों को ठहराने के लिए अनेक शामियाने, कनातें आदि बुक की गई हैं. उनमें से कुछ ने हाल ही में अपने संघर्षों के सफलतापूर्वक फैसले हासिल किए हैं और कुछ अभी भी संघर्षरत हैं.

समूचे देश में डेलीगेटों के सफर पर होने वाले खर्चों के लिए धन जुटाने के लिए अभूतपूर्व उत्साह है. अनेक यूनियनों ने चौथे सम्मेलन को लोकप्रिय बनाने के लिए दीवारों पर नारे आदि लिखें हैं. हिंद मोटर्स के 30 डेलीगेटों ने सड़क द्वारा कलकत्ता से मद्रास जाने की योजना बनाई है और रास्ते में वे सीटू की नीतियों को बताने के लिए मीटिंगें करेंगे.

इस सम्मेलन की विशेषता यह होगी कि बहुत बड़ी संख्या में महिला कामगार कर्मचारियों का अखिल भारतीय सम्मेलन होगा जिसमें 1,000 महिला डेलीगेट भाग लेंगी और उनमें से कुछ सीटू सम्मेलन में भी भाग लेंगी.

कामरेड बी. टी. रणदिवे का अध्यक्षीय भाषण, कामरेड पी. राममूर्ति की महासचिव की रिपोर्ट और कामरेड एम. के. पंधे की कार्य और संगठन की रिपोर्ट सम्मेलन में बहस का आधार होंगी.

सम्मेलन के दस्तावेज अंग्रेजी के अलावा हिंदी, बंगला, मलयालम, तमिल, तेलगू और मराठी में भी अनूदित किये जा रहे हैं ताकि डेलीगेटों को ये दस्तावेज अपनी ही भाषाओं में मिल सकें. सीटू शुरूआत से ही ऐसा करती आई है जो साधारण मजदूरों के लिए कोई और ट्रेड यूनियन नहीं करती. हालांकि इसमें काफी काम करना पड़ता है, लेकिन राज्य कमेटियों के सक्रिय सहयोग से यह काम सफलता-पूर्वक पूरा हो गया.

अनुवाद के विस्तृत प्रबंध के कारण हर डेलीगेट सम्मेलन की कार्यवाही को समझ पायेगा. हर डेलीगेट समूचे देश के मजदूर वर्ग के एकजुट संघर्षों के बारे में जबर्दस्त अनुभव प्राप्त करके अपने कार्य-क्षेत्रों में लोटेगा. प्रस्तावों का मसौदा डेलीगेटों को पहले ही दे दिया जाएगा ताकि समय से पहले ही वे संशोधन पेश कर सकें.

संघर्षरत मजदूर वर्ग के जुझारू प्रतिनिधियों के स्वागत और सम्मेलन की कार्यवाही को ठीक प्रकार से चलाने के लिए मद्रास में एक भारी वालिंटियर दस्ता तैयार किया गया है. ये वालिंटियर स्वयं संघर्षों की अग्नि-परीक्षा से गुजरे हैं. हाल ही में सीटू के झण्डे के नीचे मद्रास में और मद्रास के चारों ओर अनेक संघर्ष चलाए गए हैं.

मद्रास में 15 अप्रैल को एक विशाल जुलूस निकाला जाएगा और उसके बाद एक विराट सभा होगी जिसमें सीटू के फैसलों को विस्तार से बताया जाएगा.

इस सम्मेलन की जबर्दस्त सफलता के लिए सभी जोर-शोर के साथ काम में जुट जाएं. इस सम्मेलन की तैयारी के दौरान जो उत्साह पैदा हुआ है वह सम्मेलन के बाद और अधिक बढ़ेगा.

सीटू के चौथे सम्मेलन को लाल सलाम

कोलार सोना खानों में धांधली

कोलार में ऊरगांव और नंद दुर्ग सोना की खानें 1828 में मैसूर के टीपू सुल्तान के संचालन में थीं. इसके बाद ये खानें मैसर्स जोन टेलर एंड सन्स ने खरीद लीं जिसको 1876 में मैसूर में एक ज्वांइट स्टाक कंपनी में बदल दिया गया.

उन गरीब किसानों ने जिनके पास निर्वाह के कोई साधन नहीं थे अपनी जमीन इस आशा में बेच दी ताकि उन्हें अच्छा वेतन मिले और उनकी हालत सुधरे. लेकिन हालत सुधरने की बजाए और खराब हो गई. इसके बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया जिसने उनकी हालत और भी बिगाड़ दी. दुर्भाग्य से उस समय कोलार की सोना खदान में यूनियन नहीं थी जिससे वे अपनी वेतन-वृद्धि के लिए लड़ सकते. उसके बाद उन्होंने एक यूनियन बनाई और बोनस-वृद्धि के लिए जबर्दस्त संघर्ष किया. प्रबंधकों को उनकी मांगे माननी पड़ी और बोनस का अधिकार भी दिया गया. यह ट्रेड यूनियन आंदोलन के द्वारा मजदूरों की पहली जीत थी.

दूसरे विश्व-युद्ध के बाद भारत 1947 में स्वतंत्र हो गया और इस समय मैसर्स जोन टेलर एंड संस ने ऊरगांव खदान को बंद करके चार हजार मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया और अधिक से अधिक मुनाफा कमाने की कोशिश की. अंततः इन कोशिशों में प्रबंधकों को सफलता मिली और ऊरगांव खदान बंदकर दी गयी और चार हजार मजदूर बेकार हो गये. नंद दुर्ग को बंद होने से बचाने के लिए मजदूरों और राजनैतिक दलों ने राज्य सरकार को इन सोना खदानों का राष्ट्रीकरण करने के लिए मजबूर किया. 1956 में इन खदानों का राष्ट्रीकरण कर दिया गया.

कोलार सोना खदानों से भारी राजस्व मिलने के कारण राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के विकास में काफी उन्नति की. लेकिन इस बहाने से कि ये खदानें ठीक तरह से काम नहीं कर रही हैं, मजदूरों की वेतन-वृद्धि बढ़ती हुई महंगाई के बावजूद भी नहीं की गई.

1962 में भारत सरकार के वित्त विभाग ने इन उत्पादन खदानों का संचालन अपने हाथ में ले लिया. दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 32 हजार मजदूर काम करते थे और इन मजदूरों की संख्या धीरे-धीरे घटाकर जब भारत सरकार ने अपने संचालन में लीं तो 23 हजार कर दी गई और जब वित्त विभाग ने इनको अपने हाथ में लिया तो चार हजार मजदूर और निकाल दिए गए. इसके बाद भी मजदूरों का नौकरी से निकाला जाना बराबर जारी है. 1972 में इन मजदूरों की संख्या उन्नीस हजार से घटाकर 13 हजार रह गई और जिसमें से अधिकतम मजदूर बहुत ही कम वेतन पाते हैं. अब यह संख्या 12113 है. अधिकतम मजदूरों का वेतन 290 रुपये से कम है. यानि इन खदानों के सरकार द्वारा अधिग्रहण के बाद भी मजदूरों की हालत बहुत चिंताजनक है. इस बढ़ती मंहगाई में और मकान किराए में वृद्धि के कारण इन मजदूरों का जीवन-निर्वाह बिल्कुल ही असंभव होता जा रहा है जिसके कारण इनको बहुत ही हानिकारक झुग्गियों में रहना पड़ रहा है जिनके चारों ओर गंदगी के ढेर अक्सर पाए जाते हैं.

अब यह मजदूर संगठित रूप से अपना आंदोलन चला रहे हैं. कोलार सोना प्रबंधकों ने मजदूरों के खिलाफ बदले की भावना का रवैया अपनाया हुआ है. उन्होंने वेतनों में बढ़ोतरी करने के बजाए उन पर चोरी के व अन्य झूठे इलजाम लगाने शुरू कर दिए थे. प्रबंधक चोरी के झूठे इलजाम पर मजदूरों को नौकरी से निकाल देते हैं जबकि असली चोरों को वह सुरक्षा देती है. हाल ही में सुना गया है कि नंद दुर्ग के स्मैलटिंग हाउस से 12 लाख रुपये का सोना गायब हो गया है. कहा गया है कि इसके अति-

[शेष पृष्ठ पंद्रह पर]

कोयला : हड़ताल की तैयारी

सीटू, एटक, बी. एम. एस. इंटक और एच. एम. एस. ने 28 मार्च को निम्नलिखित संयुक्त प्रेस बयान जारी किया है.

हम कोयला उद्योग के संयुक्त द्विपक्षीय समिति में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि समझौते की धीमी गति का कड़ा प्रतिरोध करते है जिससे फैसले की निकट भविष्य में आशा नहीं.

हमें बड़ी आशा थी कि पिछले 5 फरवरी को हुई 6 लाख कोयला खदानों के मजदूरों की एक दिन की अखिल भारतीय पैमाने पर हुई शानदार हड़ताल के पश्चात प्रबंधक, मजदूरों की सशक्त भावनाओं की कद्र करके एक ठोस और सुनिश्चित निर्णय पर पहुंचेंगे लेकिन प्रबंधकों की उदासीनता ने हमारी आशा पर पानी फेर दिया.

हम प्रबंधकों और ऊर्जा मंत्रालय से अनुरोध करते हैं कि वे समस्त प्रश्नों पर गंभीरतापूर्वक विचार करें और 19-20 अप्रैल, 1979 को होने वाली जे. बी. सी. सी. आई. की बैठक में ठोस प्रस्ताव लाएं जो मजदूरों को स्वीकार्य हों.

हम अपने पहले के निर्णय को दोहराते हैं कि अगर प्रबंधकों ने हमारी मांगे नहीं स्वीकार की तो हम अनिश्चतकालीन हड़ताल करेंगे.

अतः हम प्रबंधकों को चेतावनी देते हैं कि अगर वे जे. बी. बी. सी. आई. की आगामी बैठक में तर्क संगत रूप से स्वीकृत प्रस्तावों को सामने नहीं लाते हैं तो केंद्रीय ट्रेड यूनियन को हड़ताल की तैयारी करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह जाएगा, जिससे कि वे उनसे मजदूरों की न्यायिक मांगों को मनवा सकें.

अतः हम अखिल भारतीय कोयला खदान मजदूरों से अपील करते हैं कि वे ऐसी हड़ताल की कार्यवाही की तैयारी शुरू करें.

सीटू के राज्य सम्मेलनों का संक्षिप्त विवरण

सीटू के चौथे सम्मेलन की तैयारी के रूप में सीटू को राज्य, जिला व स्थानीय स्तर के सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, इन सम्मेलनों में विभिन्न कमेटियों के कार्यों की रिपोर्टें पेश की जा रही हैं और उन पर बहस हो रही हैं. सीटू केंद्र को प्राप्त समाचारों की अनुसार इन सम्मेलनों में हजारों मजदूर भाग ले रहे हैं. मजदूर वर्ग में एक नया उत्साह पैदा हो रहा है. यहां हम कुछ बहुत ही सक्षिप्त रिपोर्टें दे रहे हैं.

आसाम में सीटू का प्रभाव बढ़ा

आसाम में सीटू की बढ़ती हुई लोकप्रियता, सीटू के आसाम राज्य कमेटी के तीसरे सम्मेलन ने बहुत अच्छी तरह से दर्शाया है. यह सम्मेलन 8 से 11 मार्च तक नाहरकटिया में हुआ. नाहरकटिया एक छोटा सा शहर है जो अपर आसाम में तेल, चाय, बिजली, खाद और प्लाईवुड का औद्योगिक केंद्र है.

इस सम्मेलन में 17 महिला डेलीगेटों और बिरादराना डेलीगेटों से 315 डेलीगेटों ने भाग लिया. चाय-बागान यूनियनों से आए डेलीगेटों की सबसे ज्यादा संख्या थी, ये 137 थे. सम्मेलन की कार्यवाही चलाने के लिए एक अध्यक्ष मंडल चुना गया. कामरेड सुरेन हजारिका, घनीराम खोसला और अमिता भट्टाचर्जी इसके सदस्य थे. सीटू की आसाम राज्य कमेटी के महासचिव कामरेड अमल घोष दस्तीदार ने अपनी रिपोर्ट में बतलाया कि किस प्रकार सीटू राज्य में आंदोलनों को आगे बढ़ाने में कामयाब रही. 1975 में सदस्यता 4400 थी और यह अब बढ़ कर 1979 में 20,000 हो गई. उन्होंने कुछ कमजोरियां भी बतलाई और उनको दूर करने के सुझाव भी दिए. सचिव की रिपोर्ट पर विभिन्न समस्याओं पर खास तौर से चाय व सड़क परिवहन मजदूरों की समस्याओं पर 43 डेलीगेटों ने बहस में भाग लिया. सम्मेलन को सीटू के अध्यक्ष कामरेड बी. टी. रणदिवे ने बधाई दी. इसमें सीटू के उपाध्यक्ष और पश्चिमी बंगाल की वाम मोर्चा सरकार के मुख्य मंत्री कामरेड ज्योति बसु ने आसाम में ट्रेड यूनियन आंदोलन का अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के साथ कंधे से कंधा मिला कर आगे बढ़ने पर प्रकाश डाला. कामरेड अचिंत्य भट्टाचर्जी ने भी सम्मेलन को बधाई दी. सम्मेलन ने आसाम में मजदूरों की समस्याओं और चीन के वियतनाम पर आक्रमण का खण्डन करते हुए व शांतिपूर्वक समझौते की मांग करते हुए कई प्रस्ताव पास किये.

11 मार्च को खुले अधिवेशन में 20,000 से भी ज्यादा मजदूरों ने भाग लिया. इस सभा में कामरेड बी. टी. रणदिवे, कामरेड ज्योति बसु व अन्य नेताओं ने भाषण दिए. कामरेड बी. टी. रणदिवे ने बताया कि मजदूरों की हालत बहुत ही दर्दनाक है और इनको देश में सबसे कम वेतन मिलता है. उन्होंने मजदूर वर्ग को अपने शोषण के खिलाफ और अपने जनवादी व आर्थिक अधिकारों के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया. उन्होंने बारगोलाई में 15 खदान मजदूरों की दुर्घटना से मृत्यु हो जाने पर खेद प्रकट किया और सरकार के रवैये की आलोचना की. कामरेड ज्योति बसु ने सीटू संगठन को मजबूत बनाने की महत्ता को बतलाया. उन्होंने पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा सरकार द्वारा मजदूरों की हालत सुधारने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर भी प्रकाश डाला.

सम्मेलन ने 57 सदस्यों की एक राज्य कांऊसिल और 17 सदस्यों की एक राज्य कमेटी निर्वाचित की. कामरेड सुरेन हजारिका अध्यक्ष और कामरेड अमल घोष दस्तीदार महासचिव चुने गये.

गुजरात में सीटू की सदस्यता दोगुनी

सीटू की गुजरात राज्य कमेटी का तीसरा सम्मेलन 11 मार्च को बापू नगर अहमदाबाद में हुआ. सम्मेलन राज्य कमेटी के अध्यक्ष कामरेड बसंत मेहंदले द्वारा झण्डा फहराए जाने के बाद शुरू हुआ. डेलीगेटों ने शहीदों और बलिदान हुए नेताओं व मजदूरों को श्रद्धांजलि अर्पित की.

सम्मेलन की कार्यवाही चलाने के लिए एक अध्यक्ष मंडल चुना गया जिसके सदस्य कामरेड बसंत मेहंदले, कामरेड दिनकर मेहता और कामरेड अपाची थे सम्मेलन का उद्घाटन सीटू के सचिव कामरेड एम. के. पंधे ने किया. उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में बम्बई सम्मेलन के बाद के हालात के बारे में बताया कि किस प्रकार सीटू देश के विभिन्न भागों में अपना असर बढ़ा रही है.

अहमदाबाद, बडौदा और कांडला जैसे विभिन्न केंद्रों में चल रहे मजदूर आंदोलनों पर कई कामरेडों ने भाषण दिए. उन्होंने बतलाया कि मजदूरों में सीटू किस प्रकार लोकप्रिय होती जा रही है. सीटू की सदस्यता 1975 में 5,000 थी और अब यह बढ़कर 1978 में 11,000 हो गई है.

अहमदाबाद में नए स्वदेशी मिल के प्रोविडेंट फंड के चुनाव के दौरान सीटू को 1271 वोट मिले जबकि मान्यता प्राप्त मजूर महाजन को केवल 300 वोट मिले. महेन्द्र टैक्सटाइलस में सीटू की यूनियन द्वारा लगातार संघर्ष चलाए जाने से सीटू को आप ही मान्यता मिल गई है.

कांडला गोदी और बन्दरगाह में और न्यू फ्री ट्रेड जोन में प्रबंधकों के एजेंटों की गुंडागर्दी के बावजूद सीटू

[शेष पृष्ठ चार पर]

हरियाणा में सीटू का पहला सम्मेलन

[पृष्ठ तीन से आगे]

काफी आगे बढ़ी है. इस दौरान राज्य में सीटू एक जबर्दस्त ताकत के रूप में उभरी है.

सम्मेलन ने पुलिस दमन, औद्योगिक संबंध विधेयक, मंहगाई सूचकांक में घोखाघडी, मंहगाई और बढ़ती हुई बे-रोजगारी के खिलाफ और महिला कामगारों, खोमचे वालों, म्युनिस्पिल मजदूरों, बोनस और दैनिक वेतन पर काम करने वाले मजदूरों आदि की मांगों को लेकर प्रस्ताव पास किए.

सम्मेलन ने नई राज्य कमेटी को चुना जिसमें कामरेड बसंत मेहंदले अध्यक्ष और कामरेड परमार महासचिव चुने गए.

सम्मेलन के बाद एक सभा हुई जिसमें हजारों मजदूरों ने भाग लिया. इस सभा को कामरेड चन्दूभाई पटेल, एम. के. पंधे, मेहंदले, परमार और अन्य नेताओं ने संबोधित किया. इस सभा के बाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया.

हरियाणा सीटू का हिसार में प्रथम सम्मेलन 16, 17 और 18 मार्च को हुआ. इस सम्मेलन में 59 डेलीगेटों तथा 66 प्रेक्षकों ने हिस्सा लिया. सोनीपत और फरीदाबाद को छोड़कर जो दिल्ली राज्य कमेटी में आते हैं सभी जगहों से डेलीगेट आए थे. प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में बताया गया कि सीटू ने मजदूर वर्ग को सही दिशा दिखाई और हिसार टेक्सटाइल मिल्स हिसार की 68 दिन की महत्वपूर्ण हड़ताल को सफल बनाया. जिंदल इंडस्ट्रीज हिसार में मजदूरों ने भी सीटू का झंडा लगाया और मजदूर पर जलियांवाला कांड दुहराया गया, फिर भी ये घबराए नहीं. दूसरे ट्रेड यूनियन संगठनों ने भी इनकी मदद की. हरियाणा के अंदर मजदूर संघर्षों की किसानों ने पैसे तथा अनाज से इनकी मदद की. 11 मई 1978 को आर्थिक मांगों को लेकर प्रदर्शन हुए जिसमें भी मजदूरों ने हिस्सा लिया.

इस सम्मेलन में ट्रेड यूनियन एकता तथा जनवादी अधिकारों की रक्षा का एक प्रस्ताव पेश हुआ और सर्वसम्मति से सास हो गया. हर तरह के अधिकारों की रक्षा हो सके, इस पर बल दिया गया. सम्मेलन की कई मांगें थी, जैसे सभी उद्योगों में न्यूनतम वेतन 350 रुपये मासिक हो, मंहगाई, मकान और यात्रा भत्ता मिले, स्थाई बोनस का कानून बने, ले-आफ, छंटनी, तालाबंदी, पर रोक लगाई जाए, बेकारी भत्ता दिया जाए और सबको नौकरी मिले, प्राविडेंट फंड की अदायगी आसानी से हो, लेबर कालोनी बनाई जाए और बिजली, पानी की अच्छी व्यवस्था हो, आदि मांगें थीं

इस सम्मेलन में वियतनाम पर चीन के हमले की निंदा की गई. इसमें नये साल के नये पदाधिकारी चुने गए. कामरेड रघबीर सिंह हुड्डा अध्यक्ष और कामरेड श्रद्धानंद सोलंकी महासचिव चुने गए.

सीटू के दिल्ली में 35 हजार सदस्य

18 मार्च को शाम के 4 बजे कटला रामलीला में जलसे का आयोजन किया गया और हिसार के विभिन्न स्थानों से मजदूर लाल झंडा तथा नारे लगाते हुए इसमें सम्मिलित हुए. मुख्य वक्ता का. मेजर जयपाल सिंह ने मजदूरों को उनके संघर्षों के लिए बधाई दी और सभी मजदूर साथियों को राजनीतिक चेतना बढ़ाने के लिए कहा.

सीटू की दिल्ली राज्य कमेटी का चौथा सम्मेलन 31 मार्च और 1 अप्रैल को कर्मपुरा, दिल्ली में हुआ. इस सम्मेलन में 442 डेलीगेटों और 44 प्रेक्षकों ने भाग लिया. सम्मेलन की कार्यवाही चलाने के लिए एक अध्यक्ष मंडल चुना गया. कामरेड चाचा शादी राम, सुरज भान भारद्वाज, अजीत भट्टाचार्य, वेद प्रकाश और कामरेड कमल नारायण इसके सदस्य थे. सीटू के अध्यक्ष कामरेड बी. टी. रणदिवे ने सम्मेलन का उद्घाटन किया.

कामरेड रणदिवे ने देश की मौजूदा राजनीतिक व आर्थिक परिस्थितियों पर प्रकाश डाला और समूचे ट्रेड यूनियन आंदोलन की एकजुटता का महत्व बताया.

कामरेड जयंत राय ने रिपोर्ट प्रस्तुत की. 28 डेलीगेटों ने बहस में भाग लिया. सम्मेलन में जरूरत के आधार पर न्यूनतम वेतन,मंहगाई भत्ता, औद्योगिक संबंध विधेयक व दमन के खिलाफ और महिला कामगारों पर तथा दूसरे प्रस्ताव पास किए गए.

दिल्ली राज्य में सीटू का प्रभाव काफी तेजी से बढ़ रहा है. सम्मेलन में दी गई जानकारी के अनुसार 1978 में दिल्ली में सीटू के 33,681 सदस्य थे. यह संख्या अब और भी तेजी से बढ़ रही है.

सम्मेलन ने नई राज्य कमेटी चुनी. कामरेड चाचा शादी राम अध्यक्ष, का. सूरज भान भारद्वाज, का. बी. के. पालीवाल व का. मोहन लाल उपाध्यक्ष, का. जयंत राय महा सचिव, का. जोगेंद्र शर्मा सचिव और का. अजीत भट्टाचार्य कोषाध्यक्ष चुने गए. पदाधिकारियों सहित 31 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया.

एक अप्रैल को खुला अधिवेशन हुआ जिसमें हजारों मजदूरों ने भाग लिया. इस अधिवेशन को कामरेड बी. टी रणदिवे और पदाधिकारियों ने संबोधित किया.

कामरेड चाचा शादी राम ने दिल्ली राज्य में सीटू की भूमिका की प्रशंसा की.

सीटू की महाराष्ट्र राज्य कमेटी का तीसरा सम्मेलन 16-17 और 18 मार्च को नागपुर में हुआ.

शहीदों और बलिदान हुए नेताओं व मजदूरों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और इस बारे में प्रस्ताव भी पास किए गए.

[शेष पृष्ठ तेरह पर]

कामगार महिलाएं संघर्ष की राह पर

1978 में महिला कामगार कर्मचारियों का अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाने की घोषणा की थी. इसके बारे में हम अपने जनवरी अंक में एक रिपोर्ट दे चुके हैं. इस दौरान अखिल भारतीय सम्मेलन की तैयारी के रूप में राज्य, जिला और स्थानीय स्तर के महिला कामगार सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं.

सीटू के आह्वान पर आयोजित किए जा रहे महिला कामगार सम्मेलनों में सभी उद्योगों, नर्सों, टेलीफोन कर्मचारियों, दवा कर्मचारियों, स्कूल व कालेजों के अध्यापकों, पत्रकारों, डाक्टरों और बैंक, रेलवे, मंत्रालीय, म्युनिसिपैलिटी, इंकम टैक्स, बीमा, हाउसिंग बोर्ड, प्रोविडेंट फंड, डाक-तार, ट्रांसपोर्ट, कारखाने, खदानों व बागान मजदूरों व अन्य सभी किस्म के संस्थानों से महिलाएं बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही है.

महाराष्ट्र

4 मार्च को बंबई में महिला कामगार कर्मचारियों का सम्मेलन हुआ. इसमें महाराष्ट्र के विभिन्न भागों से 1200 महिला कामगार कर्मचारियों ने भाग लिया जिसमें 350 से भी ज्यादा विभिन्न ग्रामीण जिलों से आई. इसमें से अधिकतम खेतिहर मजदूर, बीड़ी मजदूर और आदिवासी थीं.

डा. चन्द्रकला बेहटे ने सम्मेलन का उदघाटन किया. कामरेड अहिल्या रंगनेकर, संसद सदस्या ने, सम्मेलन की अध्यक्षता की. उन्होंने महिला कर्मचारियों की खतरनाक हालतों पर प्रकाश डाला और खेतिहर और असंगठित उद्योग क्षेत्रों के मजदूरों की हालतों के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि 31 वर्षों की आजादी के बाद जिसमें 11 वर्ष का एक महिला प्रधानमंत्री का शासन शामिल है, महिलाओं की हालत बद से बदतर होती जा रही है. उन्होंने कहा कि इन हालतों को मद्देनजर रखते हुए देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली को पूरी तरह बदलने और एक सार्वजनिक मजदूरों और किसानों की सरकार कायम करने के अलावा और कोई विकल्प इन बिगड़ती हालतों को सुधार नहीं सकता. आर्थिक ढांचे में केवल जबर्दस्त बदलाव ही जनता के जीवन में सुधार ला सकता है. उन्होंने महिलाओं को एकजुट होकर अपने काम व निर्वाह की हालतों में सुधार, जनवादी अधिकारों व अपनी मांगों के लिए एकजुट संघर्ष के लिए आह्वान किया.

देवयानी डांगे ने 20 सूत्री मांग-पत्र पेश किया. इसमें महिलाओं के लिए रोजगार के समान अवसर, नौकरी की सुरक्षा, दिन में आठ घंटे का काम और सभी के लिए प्रतिदिन आठ रुपये का न्यूनतम वेतन, पुरुषों और महिलाओं के काम के लिए समान वेतन, पूरे वेतन के साथ चार महीने की प्रसूती के लिए छुट्टी, काम के दौरान बच्चों के लालन-पालन के लिए स्थान की व्यवस्था, किसी भी तरह के भेदभाव को खत्म करने, महिला कामगार कर्मचारियों के लिए सस्ते होटल्स, विवाहित महिलाओं के खिलाफ किसी भी भेदभाव को किसी भी तरह की नौकरों में लाने आदि की मांगें शामिल हैं. इस मांग-पत्र पर 31 महिलाओं ने बहस की और मांग-पत्र सर्वसम्मति से पास किया गया. इसके अतिरिक्त उन्होंने औद्योगिक संबंधी विधेयक के खिलाफ, इस बजट में करों की वृद्धि के खिलाफ और रेल सीजन किरायों में वृद्धि के खिलाफ, इंगलैंड में एशियन महिलाओं पर किए जाने वाले कौमार्य-परीक्षण के खिलाफ और महिला कामगार परिषद को स्थाई बनाने के समर्थन में प्रस्ताव पास किए. कामरेड अहिल्या रंगनेकर के संयोजन में सम्मेलन के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए तदर्थ कमेटी बनाई गई.

8 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन भी है, कीमतों में बढ़ोतरी व सीजन टिकटों में वृद्धि के खिलाफ एक प्रदर्शन करने का फैसला लिया गया था जिसके अनुसार 8 मार्च को महाराष्ट्र की महिला कामगार कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया.

आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश में महिला कामगार कर्मचारियों का राज्य सम्मेलन विजयवाड़ा में 11 फरवरी को हुआ. इस राज्य सम्मेलन से पहले कई जिला-स्तर के सम्मेलन भी हुए. इस राज्य सम्मेलन में 163 प्रतिनिधियों ने भाग लिया. विभिन्न जिला-स्तर के सम्मेलनों में एक हजार से भी अधिक महिला कर्मचारियों ने भी भाग लिया था. राज्य सम्मेलन में जहां शिक्षा और चिकित्सा संस्थाओं व दूसरे रोजगारों के प्रतिनिधि भी आये थे, वहां औद्योगिक संस्थाओं से आए प्रतिनिधियों की संख्या भी काफी थी.

अखिल भारतीय महिला कामगार कर्मचारी सम्मेलन की संयोजक कामरेड विमला रणदिवे ने सम्मेलन का उदघाटन किया और महिला कर्मचारियों की समस्याओं पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि इन कामगारों और कर्मचारियों को दिए गए अधिकार नाकाफी हैं और इन नाकाफी कानूनों को भी ठीक प्रकार से लागू नहीं किया जाता है. केंद्रीय और राज्य के सार्वजविक उद्योगों और संस्थानों में भी पुरुषों और महिला कर्मचारियों में भेदभाव किया जाता है. चार साल पहले लागू किए गए समान वेतन अधिनियम की काफी ज्यादा उद्योगों में अवहेलना की जाती है. उन्होंने सभी महिला कामगार और कर्मचारियों के लिए समान काम के लिए समान वेतन की मांग की.

इस सम्मेलन में पेश किए गऐ मांग-पत्र सर्वसम्मति से पास किया गया. महिला कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों पर 13 प्रस्ताव पास किए गए. एक प्रस्ताव द्वारा सम्मेलन ने ब्रिटिश सरकार को माफी मांगने और एशियन महिलाओं के साथ कौमार्य-परीक्षण द्वारा दुर्व्यवहार की आलोचना की. सीटू की आंध्र प्रदेश की

[शेष पृष्ठ चौदह पर]

नेपाल में 1500 भारतीय मजदूरों के हक छीने गए

कोलंबो योजना के तहत नेपाल में एक परियोजना का काम भारत का सी. पी. डबल्यू. डी. विभाग कर रहा है. इसके लिए 1964 में पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल से मजदूर भर्ती किए गए. रोजगार देते समय भारतीय मजदूरों से यह तय किया गया था कि उन्हें वही वेतन व सुविधाएं दी जाएंगी जो भारत मे मजदूरों को दी जाती हैं. सी. पी. डबल्यू. डी. के मजदूरों को 1947-1959 के बीच मिलने वाले वेतन आदि के समान अप्रैल 1970 तक उन्हें वेतन और सुविधाएं मिलती रही. 1959 के बाद वेतन आयोग की दूसरी और तीसरी रिपोर्ट आने पर भारतीय मजदूरों के वेतन व भत्तों में परिवर्तन किए गए व अन्य अंतरिम सहायता भी दी गई.

नेपाल में बढ़ती हुई महंगाई को देखकर नेपाल में वर्षों से काम कर रहे, इन मजदूरों ने भारत सरकार से यह उम्मीद की थी कि वह उनकी काम के हालातों में सुधार करेगी और वेतन वृद्धि की जाएगी. इसके बजाए मई 1970 में इन मजदूरों से भारतीय वेतनमान और भत्ते छीन लिए गए. इसको लेकर उन्होंने 4 दिन की हड़ताल की जिसके कारण न्याय की मांग करने वाले कई मजदूरों की नौकरियां छीन ली गई.

ये मजदूर बारह घंटे तक अतिरिक्त काम का भत्ता लिए बगैर काम करते थे जिससे परियोजना ठीक समय पर समाप्त हुई. इन मजदूरों ने भारत सरकार को कई माध्यमों से भारत सरकार को अपनी समस्याओं की जानकारी दी. लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. इन मजदूरों पर नेपाली मुद्रा में वेतन मान थोपे जा रहे हैं. सर्दी, चिकित्सा व अन्य भत्ते देना बंद कर दिया गया है. मजदूरों का एक परियोजना से दूसरी परियोजना में तबादला कर दिया जाता है, उनको नए सिरे से नौकरी लेने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसमें उनके वेतन में भी भारी कमी आती है. पहले जितने वेतन पर नौकरी पाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

नवंबर 1970 में ये मजदूर हड़ताल करने के लिए मजबूर हुए. अनेक नौकरी से निकाल दिए गए और कई के खिलाफ झूठे व बेबुनियाद मामले खड़े कर दिए गए. इन्होंने 19 नवंबर से 30 नवंबर तक हड़ताल और 28 से 30 नवंबर 1978 तक पांच मजदूरों ने भूख हड़ताल की. स्थानीय अधिकारियों के कहने पर कि भारत सरकार उनकी समस्याओं का हल निकाल रही है, हड़ताल वापस ले ली गई. एक दिसबंर 1978 को आवास मंत्री श्री सिकंदर बख्त को एक ज्ञापन दिया गया और उन्होंने मजदूरों की जायज मांगों को जल्द ही तय करने का आश्वासन दिया. लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ. इन मजदूरों ने मजबूर होकर 21 फरवरी से टूल डाऊन हड़ताल की. हड़ताल पूरी तरह से शांतिपूर्ण और अनुशासनबद्ध है. लेकिन अधिकारी इन्हें डराने-धमकाने और तंग करने की नीति अपना रहे हैं.

मजदूरों की एकता और उत्साह को तोड़ने के लिए प्रोजेक्ट अधिकारियों ने कैम्प में और प्रोजेक्ट क्षेत्र में मजदूरों को तंग व आतंकित करने के लिए स्थानीय पुलिस को नियुक्त कर दिया है. बिलकुल तानाशाही रवैये के अलावा वहां कोई भी जनवादी पद्धति नजर नहीं आती. सीटू इस बात की मांग करती है कि सभी तानाशाही नीतियों को एकदम खत्म कर

[शेष पृष्ठ ग्यारह पर]

'भेल' कर्मचारियों की 6 अप्रैल को हड़ताल

सीटू व दूसरी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और 'भेल' के कर्मचारियों व मजदूरों की यूनियनों ने 17 मार्च को निम्नलिखित सयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी की है.

हम भारत के सभी 'भेल' कर्मचारियों को 8 फरवरी 1979 को एकजुट अखिल भारतीय विरोध दिवस मनाने और 'भेल' प्रबंधकों द्वारा 'भेल' कर्मचारियों के नए वेतन समझौते के प्रश्न पर अपनाई गई सुस्त नीति का कड़ा विरोध करने के लिए बधाई देते हैं. दिल्ली में 16 मार्च 1979 को हुई संयुक्त समिति की बैठक किसी भी फसले पर पहुंचने में कामयाब नहीं हुई क्योंकि ट्रेड यूनियनों द्वारा दिए गए मांगपत्र की किसी भी मांग पर ठोस रूप से विचार करने के लिए 'भेल' प्रबंधकों ने इंकार कर दिया. इस प्रकार का बर्ताव स्वाभाविक रूप में 'भेल' कर्मचारियों में असंतोष बढ़ा रहा है. हमें यह देख कर बहुत ही दुःख हैं कि कर्मचारियों की जायज मांगों पर विचार करने के लिए 'भेल' प्रबंधकों ने इंकार कर दिया है.

समझौतों में ब्यूरो आफ पब्लिक एंटरप्राइजेज और सरकार हस्तक्षेप कर रही हैं जिसके कारण इसमें रुकावट आ गई हैं. हम हस्तक्षेप का कड़ा विरोध करते हैं जो सार्वजनिक उद्योग में द्विपक्षीय समझौता वार्ता को नाकामयाब कर रहा है.

हम मांग करते हैं कि 'भेल' कर्मचारियों के वेतन मौजूदा स्तर से 25/- बढ़ाए जाएं ताकि ढांचा तैयार किया जा सके जो पिछले समझौते के समाप्त होने के 2 बर्ष बाद भी बिना किसी फैसले के ऐसे ही पड़ा है.

इसलिए हम सभी 'भेल' कर्मचारियों का आह्वान करते हैं कि मौजूदा वेतन में 26% की वृद्धि की मांग को बिना किसी देरी के मनवाने के लिए 6 अप्रैल, 1979 को एक दिन की हड़ताल करें.

हमें विश्वास है कि भारत के सभी 60 हजार 'भेल' कर्मचारी इस आह्वान का शानदार जवाब देंगे ताकि प्रबंधक और सरकार 'भेल' कर्मचारियों के बाकी मामलों पर समझौता करनें की आवश्यकता महसूस करें.

सार्वजनिक उद्योग : समझौता वार्त्ताओं में लफ्फाजी

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में मजदूरों का बढ़ता हुआ आंदोलन भूतलिंगम की बेकार रिपोर्ट की सिफारिसों और ब्यूरो आफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (बी. पी. ई.) द्वारा द्वि-पक्षीय वेतन समझौता वार्ता में जबर्दस्त दखलंदाजी की चुनौती का सामना कर रहा हैं. सरकारी आंकडों के अनुसार अकेली केंद्रीय सरकार की मलकियत के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में जिनमें रेलवे, डाक-तार. सुरक्षा आदि शामिल हैं, लगभग तेईस लाख श्रमिक कार्यरत हैं. इसके अतिक्ति कई उद्योग राज्य सरकारों की मलकियत में हैं. लेकिन विभागीय उद्योगों के वेतन मान तीसरे वेतन आयोग के द्वारा निश्चित किए जाते हैं और ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के साथ समानता के लिए संघर्ष कर रहे हैं. इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के श्रमिकों की काम व निर्वाह की हालतें तुरंत ही एक खास हमले का निशाना बन रही हैं.

अखिल भारतीय सम्मेलन

15 मई, 78 को नई दिल्ली में आयोजित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में यूनियनों का अखिल भारतीय सम्मेलन सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के खिलाफ इस रवैये का प्रतिरोध करने का इसलिए पहला जबर्दस्त कदम था. इस सम्मेलन ने भूतालिंगम पैनेल रिपोर्ट की, जिसका खास मकसद मजदूर-वर्ग पर वेतन-जाम थोपना था. जबर्दस्त आलोचना की. इसने सामूहिक सौदेबाजी में सरकार और बी. पी. ई. की दखलदाजी को तुरंत खत्म किए जाने की मांग की. सम्मेलन ने यह घोषणा की कि विभागीय उद्योगों के श्रमिकों के साथ उनके वेतन, बोनस और अन्य भत्तों के मामलों में भेदभाव नहीं बरता जा सकता.

हड़ताल का फैसला

28 जून, 78 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल का फैसला सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में श्रमिकों के आम मुद्दों पर पहला जबर्दस्त संघर्ष था. सार्वजनिक क्षेत्र में आंदोलन पर हुए सम्मेलन की शक्ति और महत्ता को महसूस करते हुए केंद्रीय सरकार ने 26 जून को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की दिल्ली में एक बैठक बुलाई और इसमें आश्वासन दिया गया कि ब्यूरो कोई भी एक तरफा नियमावली जारी नहीं करेगा. केंद्रीय ट्रेड यूनियनें इस आशा के साथ कि सरकार अपने वायदे को निभाएंगी, हड़ताल वापस लेने के लिए सहमत हो गई.

लेकिन अगस्त के अंत तक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को फैसला भेजा भी नहीं गया था. एक सितबंर की मीटिंग में ट्रेड यूनियनों को दिए गए दस्तावेजों से यह साफ जाहिर था कि सरकार ने भूतालिंगम पैनेल रिपोर्ट पर पहले से ही काम करना शुरू कर दिया था. केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के पास मीटिंग में एजेन्डा पर बहस करने के लिए मना करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था.

बेईमानी

पहली सितबंर की मीटिंग के बाद भी सरकार ने ईमानदारी के साथ व्यवहार नहीं किया. ब्यूरो द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधकों को भेजे गए एक सरकुलर से साफ जाहिर होता है कि ब्यूरो द्वारा जारी की गई सभी नियमावली अभी भी लागू हैं. ट्रेड यूनियनों की एकजुट मांग के बावजूद सरकार ने इस घृणित सरकुलर को वापस लेने से इंकार कर दिया.

बी. पी. ई. द्वारा हाल ही में बुलाई गई केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की दो बैठकों में किसी भी मामले पर गंभीरतापूर्वक वार्ता नहीं हुई क्योंकि सरकार मजदूरों की मांगों को स्वीकार किए बिना विचार-विमर्श का केवल दिखावा करना चाहती थी.

बैंक और बीमा

सरकार ने बैंकों में तो पहले से ही वेतनमान के एक खास स्तर के बाद बढ़े निर्वाह-व्ययों के निराकरण के लिए घटती हुई दर लाद दी है. ऐसे ही प्रस्ताव जीवन-बीमा कर्मचारियों पर भी लादे जा रहे हैं. बीमा-कर्मचारियों के बोनस को जबरदस्त खतरा पैदा हो गया है और उनकी यूनियनें इन बर्बर हमलों के खिलाफ सीधे कार्यवाही करने की योजना बना रही हैं.

साजिश

बंगलोर में स्थित सार्वजनिक उद्योगों में ऐसे समझौते को थोपे जाने ने जो कर्मचारियों के हित में नहीं हैं, श्रमिकों के हित को न केवल बंगलोर में बल्कि सारे देश में नुकसान पहुंचाया है. हर वेतन-समझौता-वार्ता में प्रबंधकों द्वारा यह समझौता पेश किया जा रहा है और हर जगह यूनियनों को बंगलौर का यह "मॉडल" मानने के लिए कहा जा रहा है. बंगलोर फैसले में भूतलिंगम पैनल की सिफारशों का लागू किया जाना साफ जाहिर होता है. मामूली वेतन, तुच्छ सुविधाएं और रुपये 1.30 प्रति प्वाइंट मंहगाई-भत्ता इस समझौते की मुख्य बातें हैं. बंगलौर के श्रमिक भी अब यह मान रहे हैं कि उन्हें ठगा गया है.

सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उद्योगों में वेतन समझौता वार्ताएं रोक दी गई हैं. इस्पात उद्योग में हालांकि पिछला समझौता 31 अगस्त, 1978 को खत्म हो गया है. नये समझौते के लिए बात-चीत अभी जारी है, लेकिन इसका कोई फल सामने नजर नहीं आ रहा है. यदि प्रबंधकों का यह अड़ियल रवैया जारी रहता है तो दो लाख चालीस हजार इस्पात मजदूरों को सीधे कार्यवाही करनी होगी.

कोयला, 'भेल' व अन्य

कोयला खदानों में छः लाख मजदूरों ने पांच फरवरी, 1979 को प्रबंधकों द्वारा अपनाई गई देर करने वाली नीतियों और बी. पी. ई. तथा सरकार द्वारा समझौता-वार्ता में दखलंदाजी के खिलाफ

[शेष बारह पृष्ठ पर]

'भैल'-सीमेंस षड़यंत्र

पिछले अंक से हमने 'भेल'—सीमेंस षड़यंत्र पर एक लेखमाला शुरू की है. पहले लेख में हम यह बता चुके हैं कि यह साजिश किस दौर से गुजरी है और किस तरह से इसके पीछे निजी स्वार्थ काम कर रहे हैं. देश को कितना नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा यह भी हम बता चुके हैं. मौजूदा लेख में हम उन बेतुके तर्कों का खुलासा पेश कर रहे हैं जो 'भेल' प्रबंधक अपना मुंह छिपाने के लिए दे रहे हैं.

महाराष्ट्र में टाटाओं द्वारा विश्व बैंक की सहायता से 500 मेगावाट का एक सुपर थरमल पावर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है. इस सहायता की शर्त के मुताबिक सारे यंत्रों के लिए विश्व-टैन्डर मंगाने होंगे. किन्तु उसमें से 'भेल' तक के टरबाइनों के लिए किया गया था. किंतु बड़े ही आश्चर्य की बात है कि इस 'सहयोग-समझौते' को ढाई साल से ज्यादा हो गये हैं लेकिन किसी भी प्रकार की जानकारी हासिल करने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया होगा. यदि इन सब लागत और खर्च का सही हिसाब-किताब किया जाय तो सोवियत संघ के डिजाइन पर बनने वाले मौजूदा 200 मेगावाट के टरबाइन कहीं ज्यादा सस्ते है.

पोलेंड के प्रस्ताव को ठुकराया

दूसरी खामी यह बताई गई है कि 2 पारियों में इन टरबाइनों को चलाने में काफी दिक्कतें आती हैं. लेकिन यह मार्के की बात है कि पोलेंड में

पश्चिम जर्मनी के यंत्र जबरन भारत पर थोपे जा रहे हैं

प्रबंधकों और उद्योग मंत्रालय के सलाहकारों द्वारा इन यंत्रों की सूची में से टरबाइन निकाल दी गई है. ये 'क्राफ्ट-वेर्के यूनियन' से खरीदी जाएंगी क्योंकि विश्व-बैंक सहायता केवल विश्व-टैन्डर द्वारा मंगाई गई चीजों के लिए ही है. इसलिए टरबाइन के लिए सहायता पश्चिम जर्मनी की सरकार करेगी. इसक मतलब यह है कि एक टरबाइन के दाम जो 'क्राफ्ट-वेर्के यूनियन' कहेगी, वही दाम देने होंगे, चाहे टरबाइन के गुण कैसे भी क्यों न हो. कुछ यंत्र इसमें से अमरीकी कम्पनियों से भी खरीदे जाने हैं.

टाटा इंजीनियरों के अनुसार अमरीकी यंत्रों और क्राफ्ट वेर्के यूनियन के टरबाइन को जोड़ने में काफी अतिरिक्त काम करना पड़ेगा. पिछले लेख में हम यह बतला चुके हैं कि श्री कृष्णामूर्ति ने 5 जून, 1974 को अपने नोट में लिखा था कि 500 मेगावाट के टरबाइन की जानकारी प्राप्त करना इसलिए जरूरी है कि हमारी 'भेल' की प्रयोगशालाओं को अभी ठीक ढंग से काम करने में समय लगेगा और 1980 तक हमें 500 मेगावाट के टरबाइनों की बहुत सख्त जरुरत है. उन्होंने यह भी कहा था कि 500 से 800 मेगावाट तक के जेनरेटर बनाने में इससे हमें सहायता मिलेगी. लेकिन समझौता 200 से लेकर 1,000 मेगावाट गया और फिर 500 मेगावाट के यंत्रों के लिए मार्किट कोई भी नहीं है. इसलिए समझौता करना केवल एक बहाना था. यह जाहिर है कि कुछ स्वार्थी लोग इस समझौते के जैसे तैसे किए जाने के पीछे काम कर रहे थे.

बेबुनियाद खामियां

सोवियत संघ की सहायता से बनाए जाने वाले 200 मेगावाट के टरबाइनों की 'भेल' ने काफी प्रशंसा की है. और ओब्रा व बदरपुर में लगाए गए प्रोजेक्ट ठीक ढंग से काम कर रहे हैं लेकिन 500 मेगावाट के जेनरेटर बनाने की जरुरत का बहाना कर उन्होंने सोवियत संघ की सहायता से बनाए जाने वाले टरबाइनों में 3 खामियां निकाली. इन खामियों की वास्तव में कोई बुनियाद नहीं है. 'भेल' के उच्च प्रबंधकों का कहना है कि सोवियत डिजाइन के टरबाइन ज्यादा खर्चीले हैं क्योंकि इसमें ईधंन की खपत ज्यादा होती है. लेकिन जो 'क्राफ्ट वेर्के यूनियन' के सहयोग से प्लांट लगाए जाने हैं, उसपर कितना खर्च होगा, उसपर कितनी विदेशी मुद्रा लगेगी ? उस टरबाइन की क्या कीमत होगी ? यह लागत अवश्य ही क्राफ्ट वेर्के डिजाइन पर बने वर्तमान मौजूदा लागत से कहीं ज्यादा होगी और इसमें 15% का मौजूदा बैंक ब्याज भी शामिल करना सोवियत संघ डिजाइन के टरबाइन ही काम कर रहे हैं. उन्होंने अपने शोध और विकास कार्य से उनमें परिवर्तन भी किए हैं और इन परिवर्तनों के लिए हमारे शोध और विकास विभाग ने कुछ प्रोजेक्ट भी शुरू किये थे. लेकिन उच्च प्रबंधकों ने इन सबको ठप्प कर दिया. **पोलेंड ने 'भेल' को इन टरबइनों में किए परिवर्तनों की मुफ़्त जानकारी देने का प्रस्ताव रखा.** केवल एक ही शर्त रखी गई थी कि जब तक 'भेल' फैक्ट्री उत्पादन करना शुरू न कर दे तब तक 'भेल' को सारे भारी यंत्र पोलेंड से ही खरीदने होंगे जिन्हें विश्व टैन्डरों की दरों से भी कम दर पर बेचा जाएगा. **इतने अच्छे प्रस्ताव को जिसमें 'भेल' को कुछ भी न देना पड़ रहा था, ठुकरा दिया गया.** तीसरी और अंतिम खामी कि सोवियत संघ डिजाइन विभिन्न फ्रिक्वेंसियों पर काम नहीं करते है, बिल्कुल बेबुनियाद है. सोवियत संघ और पोलेंड और ओब्रा व बदरपुर में लगे सोवियत टरबाइन विभिन्न फ्रिक्वेंसियों पर काम कर रहें हैं. 'भेल' को विभिन्न राज्य इलेक्ट्रीसिटी संस्थानों से 200 मेगावाट पावर यंत्र खरीदने के आर्डर आए हैं. उत्पादन शुरू होने तक अपने इन आर्डरों के भुगतान के लिए 'भेल' ने 'क्राफ्टवेर्के यूनियन' को उस से कम से कम 15 पूरे सैट खरीदने का वचन दिया है. 200

भारत हेवी इलैक्ट्रीकल्स को गिरवी रखने की साजिश-2

मेगावाट के क्राफ्टवेर्के के सेट मध्यप्रदेश इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड को कोरबा प्रोजेक्ट के लिए दिए जाएंगे.

बेहद नुकसान

क्राफ्टवेर्के यूनियन के सेट की सब खर्च मिलाकर कुल कीमत 12 करोड़ रुपये है. लेकिन 'भेल' ने मध्य प्रदेश इलैक्ट्रीसिटी बार्ड को 6.4 करोड़ रुपये के हिसाब से देना तय किया है जो कि सोवियत संघ डिजाइन के यंत्रों की कीमत है. मध्य प्रदेश इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड के साथ इस व्यापार में 'भेल' को सीधे-सीधे 11 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का नुकसान होगा और इन यूनिटों पर 16 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बेकार जाएगी. लेकिन भविष्य में दिए जाने वाले आर्डरों पर खरीदने वालों को 6 करोड़ रुपये ज्यादा खर्च करना पड़ेगा और भारी मात्रा में बहुकीमती विदेशी मुद्रा भी देश मे बाहर चली जाएगी.

अब इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन यंत्रों को बनाने में लगने वाले अतिरिक्त पुर्जे भी 'क्राफ्टवेर्के यूनियन' द्वारा मांगे गये मनमाने दामों पर खरीदने होंगे. सारे पुर्जे तो 'भेल' बना नहीं सकता और फिर बाद में भी कुछ पुर्जे रह जाएंगे जो क्राफ्ट-वेर्के से मंगवाने होंगे. इन पुर्जों के दाम तय नहीं किए गए हैं.

लगाए गए अंदाजे के मुताबिक क्राफ्टवेर्के डिजाइन के यंत्र बनाने के लिए हरिद्वार की फैक्ट्री में 5 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे.

लेकिन ऐसे 200 मेगावाट के 20 सेट बन चुके हैं और 35 बन रहे हैं. यह सेट उत्पादन कार्य में लगा देने के पश्चात 25 साल तक काम करेंगे जिनके लिए अतिरिक्त पुर्जों की जरुरत होगी. अगर ये अतिरिक्त पुर्जे नहीं बनाए गए तो यह प्रोजेक्ट काम करना बंद कर देंगे. इस नई तकनीक अपनाने का मतलब है कि मौजूदा फैक्ट्री के समानांतर दूसरी फैक्ट्री खड़ी करना. 1976 में समझौते से पहले 5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च का अनुमान लगाया गया था लेकिन अब 'भेल' के प्रबंधकों ने इसको 50 करोड़ रुपये का कर दिया है. उस समय हरिद्वार फैक्ट्री की सारी उत्पादन-यूनिटों की कीमत 100 करोड़ रुपये थी. इस सबके अलावा, 'भेल' की मौजूदा तकनीकि और क्राफ्टवेर्के की तकनीक में बहुत जबर्दस्त अन्तर है.

अनुभव मिट्टी में मिला

तकनीकी-विज्ञों के अनुसार, नई अपनाई जाने वाली तकनीकी से पावर को स्थिर रखना भी काफी मुश्किल है. मौजूदा तकनीक और उसमें सुधार के लिए द्वारा यह कहा जा रहा है कि इस नई तकनीकी से हमें विदेशी मंडी में सौदेबाजी में काफी फायदा होगा. लेकिन यह कहना भारतीय जनता का अपमान करना है. क्योंकि क्या हम इस तर्क को मान लें कि क्राफ्टवेर्के अपनी तकनीकी से अंतराष्ट्रीय मार्किट में होने वाली आय के एक भाग को इस समझौते के बाद 'भेल' को देना गवारा करेगी.

गुप्त बात

श्री कृष्णाभूर्ति अपने खास विश्वास-पात्रों कों यह कह रहे हैं कि इस समझोते से हमें एक नये किस्म का लाभ होगा. पश्चिम जर्मनी की इस कम्पनी ने गुप्त रूप से न्यूक्लीयर तकनीकी में सहयोग के लिए माना है. भला यह कम्पनी 'भेल' की न्यूक्लीयर स्टीम जेनरेटर बनाने के लिए अपनी तकनीक क्यों देगी. कहा गया है कि ये यंत्र त्रिरूचिरापल्ली में बनाए जाएंगे और नरोरा एटोमिक पावर प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होंगे. कहा जाता है कि कृणामूर्ति कहे रहे हैं कि एटोमिक इनरर्जी कमीशन के अध्यक्ष, डा. एच.एन. सेठना को ही इसकी जानकारी है और इस बारे में पश्चिम जर्मनी की सरकार को भी अंधेरा में रखा गया है. क्या गुप्त बात है .

कितने मजे की बात है कि यह बात 'भेल' के छोटे और बड़े सदस्यों से भी

देश के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का अपमान

इतना ही नहीं है, 200 मेगावाट के जेनरेटर जो यहां बनाए जा रहे हैं, क्राफ्ट-वेर्के यूनियन के साथ जोड़े नहीं जा सकते. अभी यह मालूम नहीं है कि क्या जेनरेटर भी 'क्राफ्ट-वेर्के यूनियन' से मंगाने की कोई योजना है. लेकिन अगर इनको भी मंगाया गया तो कितनी लागत होगी, इसका भी कोई अन्दाजा नहीं लगाया गया. अगस्त, 1976 में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर होने से पहले 'भेल-इंजीनियरों ने काफी अनुभव प्राप्त कर लिया है. क्राफ्टवेर्के की तकनीक आने पर ये सारा अनुभव मिट्टी में मिल जाएगा. शोध कार्य के अलावा, इस अनुभव पर किए गए खर्च भी मिट्टी में मिल जाएगे. 'भेल' द्वारा बनाए जाने वाले कंडेंसर भी क्राफ्टवेर्के डिजाइन में नहीं लगाए जा सकते. या तो उसे क्राफ्टवेर्के से खरीदना होगा और या उसको बनाने के नये साधन खोजने होंगे. 'भेल' प्रबंधकों कही गई, इंजीनियरों को भी मालूम है, जो कहते हैं कि कृष्णामूर्ती द्वारा विश्-वास पात्रों को ही यह बात बताई गई है. अगर ऐसी बात है तो यह गुप्त कैसे हो सकती है. इसके बारे में एक अमरीकी कंपनी ने अपनी सरकार से बात-चीत की, जिसके कारण अमरीका ने पश्चिम जर्मनी सरकार से वार्तालाप किया. पश्चिम सरकारें किसी भी विकासशील देश को

[शेष पृष्ठ दस पर]

जार्ज फर्नांडीस अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते

[पृष्ठ नौ से आगे]

किसी भी तरह की न्यूक्लीयर टैक्नोलोजी देने के पक्ष में नहीं है. ऐसी हालत में यह अलिखित गुप्त लाभ केवल बच्चों को बहकाने वाली एक कहानी है.

दोहरा चरित्र

इस समझौते की शुरूआत 1974 में हुई और अगस्त, 1976 तक चली. यह इंदिरा गांधी और उसके चमचों की तानाशाही का दौर था. इस दौरान इन चमचों की जानकारी में आए बिना कोई भी काम नहीं हो सकता था. उन्हीं दिनों तत्कालीन 'भेल' के अध्यक्ष श्री वी. कृणामूर्ति ने 'भेल' के हरद्वार हैवी फाऊंडरी एण्ड फोर्ज प्लान के उद्घाटन के लिए श्री संजय गांधी को आमंत्रित किया था, जिस पर डेढ लाख रुपये खर्च किए गए थे. इस कंपनी को, जिसको 'भेल' की कमेटी ने सबसे निचला स्थान दिया था, चुनने में इन लोगों का क्या हाथ था. आगे छान-बीन करने से पता लगाया जा सकता है. तत्कालीन प्रधानमंत्री और वाणिज्य मंत्री खुल्लमखुला बहुराष्ट्रीय कंपनियों और साम्राज्यवादियों का विरोध कर रहे थे. लेकिन वास्तव में यह विरोध शब्दों तक ही सीमित था, लेकिन कार्य-रूप देते वक्त भारत की तकनीकी और शोध विकास कार्य और वैज्ञानिकों और इंजीनियरों आदि की मेहनतों को गढ में डाल इन्हीं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को देश की अर्थव्यवस्था में घुसने दिया गया. यह उस सरकार का दोहरा चरित्र था.

जार्ज फर्नांडीज

केंद्रीय उद्योग मंत्री श्री जार्ज फर्नांडीस जब जेल में थे, इस समझौते के खिलाफ़ आवाज उठा रहे थे. लेकिन यह बात जानना बहुत जरूरी है कि इस समझौते को कार्य-रूप देने का हर फ़ैसला उनके उद्योगमंत्री बनने के बाद ही किया गया. वास्तव में क्राफ्टवेर्के डिजाइन पर 200 मैगावाट के टरबाइन बनाने का फैसला केवल इन्हीं के नेतृत्व में हुआ.

उद्योग मंत्रालय के पास 500 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए विदेशी यंत्र मंगवाने के लिए टाटा का आवेदन-पत्र पड़ा हुआ था. जनता सरकार के सत्ता में आने के बाद तक भी यह इसी तरह पड़ा रहा. लेकिन त्रिपक्षीय भारतीय श्रम सम्मेलन में, जो जनता सरकार के सत्ता में आने के बाद बुलाया गया था, 'सीटू' के महासचिव कामरेड राममूर्ति ने यह बात उठाई थी कि टाटा के इस आवेदन को स्वीकार न किया जाए. 500 मेगावाट की बजाए 200 और 110 मेगावाट के 'भेल' द्वारा बनाए गए यंत्र ही लगाए जाने चाहिए, क्योंकि 500 मेगावाट के प्लांट में अगर कोई खराबी आ जाए तो सारी पावर सप्लाई कट जाएगी जबकि दो-200 और एक 110 मेगावाट के यंत्र लगाने से इसका कोई खतरा नहीं. इन सबके बावजूद टाटा का आवेदन स्वीकार कर लिया गया है.

यह एक मार्के की बात है कि यह स्वीकृति क्राफ्टवेर्के के साथ समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद दी गई, जिससे 'भेल' प्रबंधक क्राफ्टवेर्के टरबाइन को टाटा प्रोजेक्ट पर थोपने में कामयाब होगा. अगर इस समझौते को कार्य-रुप देने का फैसला जनता सरकार नहीं करती तो समझौते का मतलब यह था कि केवल एक करोड़ रुपये का नुकसान जो कि समझौते के अनुसार तय किया गया था, इससे होने वाला दूसरा नुकसान बचाया जा सकता था. **जार्ज फर्नांडीस यह कह रहें हैं कि यह समझौता पिछली सरकार के कारण हमारे सामने है यह कह कर वे अपनी जिम्मेदारी से कट नहीं सकते.**

चितरंजन मजदूरों के संघर्ष का समर्थन

कामरेड पी. राममूर्ति. एम. पी., महासचिव, सीटू ने 26 मार्च को निम्नलिखित बयान जारी किया.

सीटू चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स (सी. एल. डब्लू) लेबर यूनियनों को रेलवे मंत्रालय द्वारा मान्यता देने और चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जैसे महत्वपूर्ण उत्पादन कारखानों में मांगों को तय करने के लिए रेलवे मंत्रालय द्वारा लगतार किए जा रहे इंकार की आलोचना करती है. असलियत में इस्पात और कोयला जैसे कई संगठित उद्योगों में मनपसंद यूनियनों को मान्यता देने का रवैया मिट चुका है. लेकिन रेलवे मंत्रालय मनपसंद यूनियनों को मान्यता देने की वही पुरानी नीतियां अपना रहा है. चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, इंटीग्रल कोच फैक्टरी जैसी उत्पादन यूनिटों में यूनियनों को मान्यता नहीं दी जा रही है जबकि जो मान्यता प्राप्त फेडरेशनों से सम्बन्ध है, उन्हें रेलवे बोर्ड स्तर पर पिछले दरवाजे से मान्यता दी जा रही है.

चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के मजदूर सी. एल. डब्लू. लेबर यूनियन के नेतृत्व में एक अरसे से मान्यता के लिए और विक्टमाइजेशन के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं. उन्होंने जनवरी, 1978 में एक सांकेतिक हड़ताल की थी. कोई भी फैसला न हो सकने के बाद एक बार फिर यूनियनों ने 28 मार्च को सांकेतिक हड़ताल करने का नोटिस दे दिया है. अधिकारी जायज मांगों पर कोई भी फैसला लेने की बजाए समाज विरोधी तत्वों के साथ मिलकर मजदूरों को आतंकित करने और एक अस्त-व्यस्त वातावरण पैदा करने की साजिश कर रहे हैं.

[शेष पृष्ठ पंद्रह पर]

भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड

तालाबंदी के लिए जिम्मेदार कौन ?

भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (बेल), गाजियाबाद रक्षा मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उद्योग है. इसमें 2400 मजदूर और 400 एग्जीक्यूटिव काम करते हैं. इसका सालाना उत्पादन 12.4 करोड़ रुपये का है. इसके प्रबंधकों ने 9 मार्च से इस कारखाने में तालाबंदी कर दी है.

प्रबंधकों का कहना है कि यहां के मजदूर और कर्मचारी 21 फरवरी से गैर-कानूनी हड़ताल पर हैं और प्रबंधकों को घेराव आदि की धमकी दे रहे हैं. लेकिन, इसकी असलियत कुछ और ही है. इसके कर्मचारी शांतिपूर्वक ढंग से अपना काम कर रहे थे. उत्पादन अधिकतम बनाए हुए थे, ये केवल अपनी छुट्टी के दौरान गेट पर प्रदर्शन करते थे, जहां पर क्रमिक-भूख-हड़ताल आयोजित की गई थी.

ये कर्मचारी 23 फरवरी से 6% नगर-प्रतिपूरक भत्ते की मांग कर रहे थे और ये भत्ता पहले ही एक सितंबर, 1977 से कंपनी के 400 एग्जीक्यूटिवों को दिया जा चुका है. इस तालाबंदी का वास्तविक कारण यह है कि प्रबधक वायु-सेना, रेलवे, इंडियन आयल कार्पोरेशन, पुलिस, सेना और अन्य विभागों को अपने यंत्र बनाकर नहीं दे सके, जो कि इनको अपने अनुबंध के अनुसार अब तक दे देने चाहिए थे. इस सिलसिले में, प्रबंधकों के साथ समझौता-वार्ता चल रही थी. कर्मचारियों को बतलाया गया था कि उनकी मांगें रक्षा उत्पादन मंत्रालय के पास भेजी गई हैं. लेकिन समझौता-वार्ता पूरी करने की बजाए प्रबंधकों ने अचानक 9 मार्च, से तालाबदी घोषित कर दी और 11 ट्रेड यूनियन-नेताओं व कार्यकर्त्ताओं को झूठे आरोप लगाकर मुअत्तल कर दिया. इस तालाबंदी के कारण कंपनी को एक महीने में एक करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है जबकि इस भत्ते की मांग को पूरा करने के लिए एक महीने में 72 हजार रुपये खर्च होंगे. **कंपनी की क्या बढ़िया समझदारी है.** 'बेल' रेडार जैसे अनेक वैज्ञानिक यंत्र बनाने वाली अकेली भारतीय कंपनी है और ये यंत्र केवल ऊपर दिए गए विभागों में काम में आते हैं.

प्रबंधक ये यंत्र बनाकर देने में अपने वायदे से बहुत ही पीछे थे और अनेक विभागों को सालों से कोई सामान नहीं दिया गया जिसके कारण रेलवे, डाक व तार विभाग, पुलिस, वायु-सेना, मिलिट्री, जंगल, ट्रांसपोर्ट सबकी सेवाओं में काफी बाधा आ रही है. और मंत्रियों को प्रबंधकों द्वारा वास्तविकता से दूर रखा जा रहा है.

प्रबंधकों की ये असफलता, गलत नीतियों और कुप्रबंध के कारण है. अपना मुंह छिपाने के लिए अब इन्हीं कर्मचारियों की जायज मांगों के लिए किए जा रहे संघर्ष को हिंसात्मक बताकर तालाबंदी कर दी, ताकि ये इन विभागों को कह सकें कि तालाबंदियों के कारण हम उत्पादन नहीं कर सके. इस दौरान समझौता-वार्ता को तोड़ते हुए 'बेल कर्मचारियों को डराया और धमकाया जा रहा है और उनके संघर्ष को हिंसात्मक करार दिया जा रहा है जबकि स्थानीय सरकारी अधिकारी इस बात को मानते हैं कि 'बेल' कर्मचारियों का सघर्ष पूरी तरह शांतिपूर्ण था. यूनियनों ने उत्पादन के लक्ष्यों का पूरा करने का प्रबधकों को 7 मार्च को विश्वास दिलाया था और प्रबंधकों को यह भी कहा था कि ये उत्पादन बढ़ाने में मदद करेंगे. लेकिन प्रबंधकों की नीयत साफ न होने के कारण उनको तालाबंदी का सहारा लेना पड़ा. यह गैर-कानूनी और मनमानी तालाबदी न केवल इस कारखाने के कर्मचारियों को नुकसान पहुंचा रही है बल्कि एक सार्वजनिक उद्योग को भी 5 लाख रुपये प्रतिदिन का उत्पादन नुकसान पहुंचा रही है.

पी. राममूर्ति का बयान

सीटू के महासचिव, कामरेड पी. राममूर्ति ने इस सिलसिले में एक प्रेस बयान जारी किया जिसमें रक्षा मंत्री से यह अनुरोध किया गया है कि वे 'बेल' के मामले में हस्तक्षेप करें. इस एकतरफा तालाबंदी की आलोचना करते हुए जिस से 2500 कर्मचारी बेकार हो गए हैं, कामरेड पी. राममूर्ति ने सभी मजदूरों से 'बेल' कर्मचारियों की हड़ताल के संघर्ष के साथ एकजुट होने का आह्वान किया. 'बेल' गाजियाबाद के कर्मचारी जो मंहगाई-भत्ते की दर में वृद्धि, मूल वेतन का 25% मकान किराया-भत्ता और नगर-प्रतिपूरक भत्ता आदि के लिए लड़ रहे हैं, अपने संघर्ष को सफल बनाने के लिए एकजुट संघर्ष को और तेज कर रहे हैं.

इसके समर्थन में गाजियाबाद की विभिन्न यूनियनों ने अधिकारियों को पत्र लिखे हैं. ये मजदूर 'बेल' मजदूरों के संघर्ष का पूरा समर्थन कर रहे हैं.

नेपाल

[पृष्ठ छः से आगे]

दिया जाय. 24 मार्च को जारी किए गए एक बयान में सीटू के महासचिव कामरेड पी. राममूर्ति ने कहा है कि केंद्रीय सरकार इस मामले में तुरन्त हस्तक्षेप करे ताकि इन मजदूरों को उनके भारतीय प्रतिपक्षी मजदूरों के समान वेतन और महगाई-भत्ते आदि दिए जाएं और उन्हें स्थाई कर्मचारी के रुप में लगाया जाय. और सीटू ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि वे इन कर्मचारियों के काम व निर्वाह की चिन्ताजनक हालत की छान बीन कराए ताकि उनको सुधारने में उपयुक्त कदम उठाया जा सके.

बयान में इन 15 सौ कर्मचारियों को अपने एकजुट संघर्ष के लिए मुबारक दी गई और सीटू ने नेपाल में काम कर रहे मजदूरों के सघर्ष का समर्थन करने के लिए भारतीय मजदूरों से अपील की है.

प्रबंधकों द्वारा विश्वासघात : आमरण अनशन

राजस्थान अणु शक्ति कर्मचारियों के 9 सूत्री मांग-पत्र और उनके संघर्ष के बारे में हम अपने जनवरी अंक में लिख चुके है. इस दौरान उनकी मांगों पर कोई भी फैसला नहीं हुआ है हालांकि इस मामले में कई बैठकें हो चुकी हैं.

इस मामले में राजस्थान अणु शक्ति कर्मचारी यूनियन (सीटू) ने प्रोजेक्ट इंजीनियर को एक ज्ञापन 6 मार्च को दिया. इस ज्ञापन की प्रतियों को प्रधान मंत्री, श्रममंत्री व अन्य अधिकारियों तथा ट्रेड यूनियनों को भी भेजा गया है.

ये कर्मचारी केंद्रीय श्रममंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन को प्रबंधकों द्वारा पूरा करने की आशा से एक अरसे से इंतजार कर रहे हैं. प्रबंधकों द्वारा इन कर्मचारियों की बुनियादी और जायज मांगों को तय करने में अपनाई जा रही देर-दार करने की नीति से ये कर्मचारी उत्तेजित होते जा रहे हैं और उनकी सहनशीलता ने भी लगभग दम भर लिया है. सरकार और केंद्रीय श्रममंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन में पैदा हुआ विश्वास भी दिन-प्रतिदिन कम होता जा रहा है.

एक साल से भी पहले हड़ताल वापस ली गई थी और अब तक इन कर्मचारियों के मांग-पत्र पर कोई भी समझौता नहीं हुआ है. यह प्रबंधकों के मजदूर वर्ग विरोधी और गैर जिम्मेदाराना रवैये को साबित करता है.

इन हालतों में अपनी लम्बे अरसे से चल रही मांगों पर तुरंत समझौते के लिए प्रबंधकों पर दबाव डालने के लिए यूनियनों ने 12 अप्रैल से शांतिपूर्वक क्रमबद्ध भूख हड़ताल शुरू की.

यूनियनों ने अपने ज्ञापन में प्रबंधकों को यह साफ जाहिर कर दिया था कि अगर 18 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो उनके पास अपने संघर्ष को तेज करने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाएगा. और ये 19 मार्च से आमरण भूख हड़ताल शुरू कर देंगे जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रबंधकों पर होगी. यूनियन ने फिर से अनुरोध किया था कि राजस्थान अणु शक्ति के प्रबंधक केंद्रीय श्रममंत्री के आश्वासन को लागू करें और कर्मचारियों की जायज मांगों पर फैसला करें ताकि प्रोजेक्ट में अच्छी औद्योगिक शांति स्थापित की जा सके. लेकिन प्रबंधकों ने इस पर कोई दिलचस्पी नहीं ली और 19 मार्च से यूनियन के अध्यक्ष कामरेड सीताराम शार्दुल ने सरकार के आश्वासनों को विश्वासघाती और प्रबंधकों की मजदूर वर्ग विरोधी नीतियों के खिलाफ आमरण अनशन जारी कर दिया हैं.

पी. राममूर्ति का बयान

इस मामले में सीटू के महासचिव कामरेड पी. राममूर्ति ने एक बयान में कहा कि मजदूरों के असंतोष के कारण अगर कोई भी अप्रिय घटना होगी तो उसके लिए प्रबंधक पूरी तरह जिम्मेदार होंगे.

उन्होंने प्रधानमंत्री से, जो इस संयंत्र के इंचार्ज हैं, अनुरोध किया कि वे रावतभाटा परमाणु संयंत्र के प्रबंधकों को केंद्रीय श्रममंत्री के सुझाव को लागू करने के लिए बाध्य करें. इस तरह स्थिति को आगे बढ़ने से बचाया जा सकता है.

सार्वजनिक उद्योग

[पृष्ठ सात से आगे]

हड़ताल की. अगर प्रबंधक कोयला खदान मजदूरों के अच्छे जीवन-स्तर को बनाने के लिए मना करने की नीति जारी रखता है तो कोयला उद्योग में सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का फैसला कर लिया है.

इसी प्रकार के मुद्दों पर भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स के साठ हजार श्रमिकों ने छ: अप्रैल को एक दिन की हड़ताल करने का फैसला कर लिया है. अगर प्रबंधक अपने रवैये को जारी रखते हैं तो इससे आगे भी कार्यवाही की जा सकती है.

हिंदुस्तान टेलीप्रिंटर्स, बालमेर लारी और हिंदुस्तान केबल्स के मजदूरों के अनुभव यह दिखाते हैं कि यूनियनों और प्रबंधकों में हुए समझौते को लागू करने के लिए हड़ताल करनी पड़ती है क्योंकि बाद में इसके लागू किए जाने में बी. पी. ई. के उच्च अधिकारियों ने अड़चनें डाली.

सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों में यह भावना स्वाभाविक ही फैल रही है कि 28 जून, 1978 की अखिय भारतीय हड़ताल को वापस लेने में वे सरकार द्वारा ठगे गए हैं. सार्वजनिक क्षेत्र में कई यूनियनें इन प्रस्तावों को लेकर पहले ही आगे आ गई हैं कि एक बार फिर अपनी मांगों के लिए एकजुट होकर संघर्ष की तैयारी की जाए.

सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी अब इस बात को महसूस कर रहे हैं कि आम वेतन-जाम की नीति बदलने के लिए जहां-तहां के अकेले संघर्ष सरकार पर दबाव डालने में नाकाफी हैं प्रबंधक जहां तहां होने वाले अकेले संघर्षों में मजदूरों को छिन्न-भिन्न करने की और झुकने के लिए मजबूर करने की जबर्दस्त कोशिश कर रहे हैं.

कई मुख्य केन्द्रों में सार्वजनिक क्षेत्रों के कर्मचारियों की ताल-मेल कमेटी मैदान में कूद पड़ी हैं. लेकिन अखिल भारतीय ताल-मेल का ठीक तरह से विकास अभी होना है.

इसलिए यह जरूरी है कि सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की वेतन-जाम और बी. पी. ई. की दखलंदाजी के खिलाफ नये देशव्यापी संघर्ष के लिए फिर से तैयारी करनी होगी और इसके बिना उनकी मांगें नहीं मनवाई जा सकती. इस मामले में सरकार की नीति को धराशायी करना ही सार्वजनिक उद्योग में समझौता-वार्ता के मौजूदा मजाक को खत्म कर सकता है.

—एम. के. पंधे

इस्पात : बी. पी. ई. की आलोचना

इस्पात मजदूरों के वेतन और दूसरी काम की हालतों पर चल रही समझौता-वार्ता स्टील आथोरिटी आफ इंडिया (सेल) और टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी द्वारा अपनाए गए रवैये के कारण लंबी खींची जा रही है. इसलिए इस्पात उद्योग के दो लाख चालीस हजार मजदूरों का उत्तेजित होना स्वाभाविक ही है. ब्यूरो आफ पब्लिक एंटरप्राइजेज इस समझौता-वार्ता में दखलंदाजी कर रहा है जिसके कारण इस्पात उद्योग की राष्ट्रीय संयुक्त परामर्श संबंधी कमेटी (एन.जे.सी.सी.) में द्विपक्षीय बातचीत में एक तरह से रुकावट आ गई है.

सी.आई.टी.यू. के अध्यक्ष कामरेड बी.टी. रणदिवे ने इस मामले में 16 मार्च को एक बयान जारी कर इस रवैये की कड़ी आलोचना की है और इस्पात मंत्रालय व "सेल" अधिकारियों से अपना मौजूदा रवैया छोड़कर ऐसे प्रस्ताव पेश करने की अपील की है जिससे और देरी के बिना समझौता तय हो जाए.

सीटू यह आशा करता है कि इस्पात प्रबंधक इस्पात मजदूरों की मांगों पर गंभीरता से विचार करेंगे और एन.जे.सी.सी. की 27 मार्च को होने वाली आगामी बैठक में कोई समझौता नहीं हुआ तो सीटू इस्पात उद्योग में सभी केंद्रीय यूनियनों से अप्रैल के महीने में किसी दिन जो ट्रेड यूनियनें तय करेंगी हड़ताल सहित सीधी कार्यवाही के लिए तैयार होने की अपील करेगी.

भारत में सभी इस्पात मजदूरों से सीटू अपील करती है कि वे अपने विभिन्न संबद्धताओं के बावजूद और एकजुट कार्यवाही जिसके कारण ही उनकी जायज मांगे मनवाई जा सकती हैं के लिए तैयार करें.

1958 में निकाले गए टिस्को मजदूरों का संघर्ष

जमशेदपुर, 5 मार्च : टाटा आयरन और इस्पात कंपनी (टिस्को) में 1958 में एतिहासिक हड़ताल हुई थी. अनेक कर्मचारियों पर झूठे अपराध लगाकर नौकरी से निकाल दिया गया. पिछले 21 सालों से ये कर्मचारी अपनी नौकरी की बहाली के लिए लड़ रहे है. उनके लंबे संघर्ष और दृढ़ संकल्प को देखते हुए टाटा उद्योग के अध्यक्ष श्री जे. आर. डी. टाटा ने 17 अप्रैल 1978 को बंबई में इन संघर्षरत मजदूरों की मांगों पर पुनर्विचार करते हुए आश्वासन दिया कि (1) 60 वर्ष से कम उम्र वाले सभी कर्मचारियों को पुनः काम में वापस ले लिया जायेगा, (2) सभी कर्मचारियों की एक और संतान को टिस्को में नौकरी दी जाएगी, बावजूद इसके कि ऐसी सहुलियत उन्हें 1967 में दी गई थी, और (3) मैनेजिंग डायरेक्टर की उचित राय के अनुसार सभी कर्मचारियों को मुआवजा दिया जाएगा.

इस आश्वासन को कार्यान्वित करने के बजाए मैनेजिंग डाउरेक्टर श्री आर. एच. मोदी ने मजदूरों की मांगों पर विचार करने से भी इंकार कर दिया. श्री मोदी की मजदूर विरोधी नीति के कारण इन कर्मचारियों ने 8 फरवरी से उनके बंगले के सामने शांतिपूर्ण ढंग से धरना कार्यक्रम चलाया.

मजदूरों की मांगों पर फिर से विचार करने की बजाए संघर्षरत मजदूरों को तंग और परेशान करने में बेशर्मी की हद को पार कर दिया गया. जिन पेड़ों की छाया में ये मजदूर बैठे थे उन्हें कटवा दिया गया, बड़े-बड़े पाइपों के द्वारा उन पर पानी फेंका गया. सुरक्षा विभाग व गुंडा विभाग ने मार-पीट की धमकियां दी. तंबू तक लगाने नहीं दिया गया.

इन परिस्थितियों से मजबूर होकर एक फरवरी से आमरण अनशन शुरू किया गया. अनशन पर बैठे कर्मचारी को 14 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया गया. उसके तुरंत बाद से दूसरा कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठा.

इन मजदूरों की मांगों को लेकर सीटू के सचिव कामरेड एम. के. पंधे ने केंद्रीय श्रममंत्री को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने के लिए अनुरोध किया है ताकि श्री टाटा द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार मजदूरों को सुविधाएं दी जा सकें.

महाराष्ट्र सीटू का तीसरा सम्मेलन

[पृष्ठ चार से आगे]

कामरेड पी. राममूर्ति ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए हाल ही में हुए ट्रेड यूनियन आंदोलन की उन्नति पर प्रकाश डाला और उन्होंने बताया कि सीटू किस प्रकार इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है.

सीटू की महाराष्ट्र राज्य कमेटी के महासचिव कामरेड पी.के. कुरने ने राज्य कमेटी के पिछले सम्मेलन के बाद की गतिविधियों का खुलासा अपनी जनरल रिपोर्ट में पेश किया. रिपोर्ट के संबंध में विभिन्न डेलीगेटों ने बहस में हिस्सा लिया और अपने अनुभवों को बताया.

सम्मेलन में विभिन्न उद्योगों में मजदूरों की समस्याओं और अन्य साधारण समस्याओं के बारे में 27 प्रस्ताव पास किए.

सम्मेलन ने नई राज्य कमेटी का निर्वाचन किया और कामरेड एस. वाई. कोल्हातकर अध्यक्ष व कामरेड पी. के. कुरने महासचिव चुने गए.

सम्मेलन के बाद एक जबर्दस्त जुलूस निकाला गया जो बाद में एक रैली में परिवर्तित हुआ. इस रैली को कामरेड पी. राममूर्ति, कामरेड ज्योति बसु, कामरेड एस. वाई. कोल्हातकर और का. पी. के. कुरने ने संबोधित किया.

महिला कर्मचारियों के राज्य सम्मेलन

[पृष्ठ पांच से आगे]

राज्य समिति के महासचिव कामरेड एन. प्रसाद राव ने इस सम्मेलन की महत्ता पर प्रकाश डाला. इस सम्मेलन ने 15 सदस्यीय कमेटी भी बनाई.

कर्नाटक

कर्नाटक में महिला कामगार कर्मचारियों ने अपने लगातार शोषण के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया है. राज्य के इतिहास में पहली बार इस प्रकार का सम्मेलन हुआ जिसमें 4 सौ प्रतिनिधियों ने भाग लिया. यह सम्मेलन मंगलौर में सीटू के नेतृत्व में मार्च में को आयोजित किया गया. आज तक महिला कर्मचारियों की गोष्ठियां केवल शहरों तक ही सीमित थीं, जिसमें पढ़ी-लिखी महिलाएं ही भाग लेती थीं और ग्रामीण महिलाओं का केवल नाम मात्र का ही प्रतिनिधित्व होता था. इस महिला कामगार सम्मेलन मे अधिकतम प्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्रों से आए थे. 80 बीड़ी कामगारों और बहुत से काफी कामगारों ने भाग लिया. इसके अतिरिक्त कुली, बागान व खेतिहर मजदूर आदि शामिल हुए और डाक्टरों, नर्सों अध्यापकों बीमा, बैंक, आल इंडिया रेडियो आदि के कर्मचारियों ने भी भाग लिया.

इस सम्मेलन में ग्रामीण महिला कामगारों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया. उन्होंने बहुत ही उत्साह और उत्तेजना के साथ जमींदारी-पूंजीवादी प्रणाली की आलोचना की.

इस 2 दिन के सम्मेलन का कामरेड बिमला रणदिबे ने उदघाटन करते हुए महिला कामगार कर्मचारियों को एकजुट होकर अपने जनबादी अधिकारों और मांगों के लिए संघर्ष करने का आहबान किया. सम्मेलन के बाद एक जुलूस निकाला गया.

इन चार सौ प्रतिनिधियों में एकसौ चालीस बिल्कुल अनपढ़ एक सौ छियालीस प्राईमरी स्कूल शिक्षा प्राप्त, 73 सैकेण्डरी शिक्षा प्राप्त, सोलह हायर सैकेण्डरी स्कूल तीन ग्रेज्युएट और उन्नीस पोस्ट ग्रेज्युएट थे.

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल की महिला कामगारों का सम्मेलन 3-4 मार्च को आसनसोल में हुआ जिसमें लगभग चार सौ प्रतिनिधियों ने भाग लिया. कामरेड मनोरंजन राय ने सम्मेलन के शुरू में झण्डा लहराया. इन प्रतिनिधियों में से चौरासी प्रतिनिधि-युनियनों की सदस्यायें थी. महिला प्रतिनिधियों ने अपने काम व निर्वाह की हालतों और समस्याओं पर बात चीत की

उन्होंने पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार और उसकी उपलब्धियों की प्रशंसा की और कहा कि ये वाम मोर्चा सरकार ही हमारी रक्षा के लिए सामने आई है. चालीस-सालों से जंगलों में काम कर रहे कामगारों ने बतलाया कि वाम मोर्चा सरकार के आने के बाद सरकार के कुशल प्रयासों से अब उनका वेतन आठ से दस रूपये प्रतिदिन हो गया है. रिजर्व बैंक के महिला प्रतिनिधि ने कहा कि हम केवल महिलाओं के लिए वेतव वृद्धि की बात क्यों करें बल्कि हमें समान काम के लिए समान वेतन और सभी को वेतन-वृद्धि देने की मांग करनी चाहिए.

कुल मिलाकर तीस प्रतिनिधियों ने भाषण दिए और एक मांग पत्र पेश किया सम्मेलन के बाद कोयला खादान क्षेत्र में एक सार्वजनिक रैली की गई जिसमें कामरेड निरूपमा चटर्जी, विमला रणदिवे आरती दास गुप्ता आदि अन्य नेताओं ने भाषण दिए- इन्होंने महिला कामगार कर्मचारियों को एकजुट होकर अपनी मांगों के लिये और जनवादी अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया.

इस राज्य सम्मेलन से पहले दुर्गापुर में जिला.स्तर का सम्मेलन छब्बीस फरवरी को हुआ जिसमें लगभग आठ सौ प्रतिनिधियों ने भाग लिया. इस सम्मेलन में इंटक से संबंधित महिला सदस्यों ने भी भाग लिया. इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल के कई जिलों में महिला कर्मचारी सम्मेलन आयोजित किये गये.

तमिलनाडु

तमिलनाडु का महिला कामगार सम्मेलन त्रिची में चार मार्च को हुआ जिसमें लगभग एक सौ पन्द्रह प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

इसमें महिलाओं के लिए घटते रोजगार के अवसरों, कम वेतन. बच्चों के लालन-पालन व प्रसूति की सुविधाएं की बेहद मांगें व दूसरे काम व निर्वाह की हालतों तथा अपने जनवादी अधिकारों के लिए विचार-विमर्श किया. इसमें आए प्रतिनिधियों ने बतलाया कि कुछ प्रबंधक कहते हैं कि अगर वो सीटू के साथ सम्पर्क छोड़ दें तो उनकी मांगें मान ली जायेगी· खादी उद्योग में काम करने वाले कामगारों का कहना है कि उनके बच्चे दस पैसे प्रतिदिन और कुछ कप चाय के लिए पूरे दिन काम करने के लिए जाते हैं. सम्मेलन में एक मांग-पत्र सर्वसम्मति से पास किया गया और अपनी सुविधाओं और वेतनवृद्धि तथा काम के निर्वाह की हालतों में सुधार, प्रसूति के लिए चार महीने की छट्टी व पूरे वेतन, चिकित्सा व अन्य सुविधाएं, बच्चों के लालन-पालन के लिए स्थान, समान काम के लिए समान वेतन, शोषण से मुक्ति आदि की मांगों को लेकर एकजुट होकर संघर्ष शुरू करने का आह्वान किया.

दिल्ली

दिल्ली राज्य का महिला कामगार कर्मचारी सम्मेलन 25 मार्च को रूपनगर दिल्ली में आयोजित किया गया. सम्मेलन की कार्यवाही चलाने के लिए कामरेड किटी मेनन, कातरेड बसंती व कामरेड बबली गुप्ता अध्यक्षमंडल की सदस्य चुनी गई. अखिल भारतीय महिला कामगार कर्मचारी सम्मेलन की संयोजक कामरेड बिमला रणदिवे मुख्य वक्ता थीं.

सम्मेलन में 192 डेलीगेटों ने भाग लिया. कामरेड रीता ने रिपोर्ट पेश की और 25 डेलीगेटों ने बहस में भाग लिया. महिला कर्मचारियों की समस्याओं व मांगों पर कई प्रस्ताव पास किए गए.

इस्पात ठेका मजदूरों का सम्मेलन

बर्नपुर में 11 मार्च को अखिल भारतीय इस्पात ठेका मजदूरों का सम्मेलन सीटू के नेतृत्व में आयोजित किया गया. इसमें 372 डेलीगेटों ने जिसमें 57 महिलायें थी भाग लिया. कामरेड बी.पी. मुखर्जी ने एक रिपोर्ट पेश की जिस पर 20 डेलीगेटों ने चर्चा की. सम्मेलन में ठेका-मजदूरों के संघर्ष पर प्रकाश डाला गया और यह भी बतलाया गया कि इस्पात मजदूरों ने अपने बहादुराना संघर्ष के साथ किस प्रकार कुछ सुविधाएं प्राप्त की है.

देश के इस्पात उद्योग में बहुत बड़ी संख्या में ठेका-मजदूर काम करते हैं. जैसे अकेले टाटा इस्पात कारखाने में 10 हजार और भारतीय आयरन और इस्पात कंपनी में साढ़े छः हजार दुर्गापुर में दस हजार और अकेले राऊरकेला इस्पात कारखाने में बीस हजार ठेका मजदूर काम करते हैं. इसके अतिरिक्त अन्य इस्पात कारखानों में अनेक ठेका मजदूर हैं. इन ठेका मजदूरों की काम और निर्वाह की हालतें बहुत ही चिंताजनक हैं. इनके वेतन और सुविधाएं कारखानों में काम करने वाले अन्य मजदूरों के समान नहीं हैं और ये वेतन विभिन्न कारखानों में अलग-अलग हैं. इन मजदूरों को आवास, पीने का पानी, चिकित्सा व अन्य सुविधाएं नामपात्र को भी नहीं हैं. महिला कामगारों की तो बहुत ही बुरी हालत है कुल मिलाकर पूरे इस्पात उद्योग में लगभग एक लाख ठेका मजदूर काम करते हैं जिनका इस्पात उत्पादन में दूसरे मजदूरों से कम योगदान नहीं है.

इस सम्मेलन में सभी इस्पात मजदूरों की एकता को कायम कर अपने काम और निर्वाह की अच्छी हालतों व मांगों को लेकर संघर्ष करने का आह्वान किया गया. सम्मेलन में हर तरह की ठेका प्रथा को खत्म करने और ठेका मजदूरों को स्थाई करने तथा उनकी दूसरे मजदूरों के समान वेतन और अन्य सुविधाएं देने की मांग की गई. और सम्मेलन ने किसी भी समय संघर्ष शुरू करने के लिए मजदूरों को तैयार रहने के लिए आवाहन किया. इसमें कहा गया है कि बारह और तेरह मार्च को संयुक्त समिति (एन जे.सी.सी) की बैठक में अगर मजदूरों के हक में कोई समझौता न हुआ तो एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की जाएगी. सम्मेलन में औद्योगिक संबंध विधेयक के खिलाफ व अन्य एकजुटता के प्रस्ताव पास किए गए.

चितरंजन मजदूर

[पृष्ठ दस से आगे]

मजदूरों को भड़काने के लिए ये समाज विरोधी तत्व लेबर यूनियनों की नीतियों के साथ गाली-गलोच कर रहे हैं ताकि कानून व व्यवस्था की समस्या खड़ी की जा सके. इतने जबर्दस्त भड़कावे के बावजूद सी. एल. डब्लू. लेबर यूनियन ने बहुत जबर्दस्त सहनशीलता दिखाई है. यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि रेल मंत्रालय ने इसमें हस्तक्षेप करने के लिए कुछ भी नहीं किया है हालांकि इस बारे में उनका ध्यान बार-बार आकर्षित किया गया है.

सीटू चितरंजन मजदूरों को अपने जबर्दस्त संघर्ष जिसे वे पिछले कई सालों से चला रहे हैं, के लिए बधाई देती है और उन्हें अपनी एकता और संघर्ष की भावना को बनाए रखने के लिए अपील करती है. सीटू सी. एल. डब्लू. के मजदूरों के जायज संघर्ष का समर्थन करती है और रेल मंत्री से हस्तक्षेप करने और मजदूरों की मांगों का फैसला करने के लिए अनुरोध करती है.

कोलार सोना खान

[पृष्ठ दो से आगे]

रिक्त जिंक की चादरों, सीमेंट, पाईप आदि चोरी कर लिए गए हैं जिनमें अफसरों का और अधिकारियों का जबर्दस्त हाथ होता है. इन चोरी की वारदातों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती बल्कि प्रबंधकों ने निर्दोष और इन गरीब मजदूरों को निकाल दिया है. इन मामलों को रफा-दफा करने की कोशिश की जाती है. सरकार भी इस मामले में प्रबंधकों का साथ दे रही है.

बिगड़ी हुई मशीनों और खदान की मरम्मत कराने और चोरी की छान-बीन करने की बजाए सरकार बार-बार यह कहे जा रही है कि ये खदान घाटे में काम कर रही हैं. खदान के मजदूरों ने इस बात की मांग की है कि चोरी के लिए जिम्मेदार लोगों को सख्त सजा दी जाए ताकि दूसरे लोग इससे प्रेरित न हो सकें और मजदूरों की मांगों को पूरा किया जा सके तथा इन्हें नौकरी से न निकाला जाए. कई लाख टन सोना खदानों से निकालने बाद भी ये नुकसान में चल रही हैं.

'दि वर्किंग क्लास' : सूचना

'दि वर्किंग क्लास' का आगामी अंक अप्रैल और मई, 1979 को सीटू के सम्मेलन के और इसका प्रकाशन-स्थल कलकत्ता से किए जाने के कारण, इकट्ठा प्रकाशित किया जाएगा. इसमें 32 पृष्ठ होंगे और एक प्रति की कीमत एक रुपया होगी.

इसके लिए सभी तरह की राशि, चैक, ड्राफ्ट, मनीआर्डर अब मैनेजर, दि वर्किंग क्लास, 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001 को भेजें इसके वार्षिक खरीद दार और एजेंट इस सूचना पर ध्यान दें.

सीटू मजदूर

सी आई टी यू का मासिक मुखपत्र

एक प्रति की दर — पचास पैसे

वार्षिक चंदा — छः रुपये

एजेंसी के लिए कम से कम पांच प्रतियां

मिलने का पता

6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001

Regd. No. D(C)-833

मद्रास में सीटू सम्मेलन में भाग लेने वाले डेलीगेटों के लिए

1. सभी डेलीगेट स्वागत कमेटी को तुरंत यह सूचना दें कि वह किस ट्रेन से मद्रास पहुंच रहे है ताकि उन्हें मद्रास सैन्ट्रल या मद्रास-बीच-स्टेशन पर मिला जा सके. पता है: 52, कुक्स रोड़, मद्रास —600912 (फोन 663 367).

2. डेलीगेट यदि वापसी के लिए टिकट रिजर्व कराना चाहते हैं तो स्वागत कमेटी के अध्यक्ष को किराये के लिए विवरण सहित उपयुक्त राशि बिना किसी देरी के भेजें ताकि टिकट-रिजर्व हो सके.

3. महिला कामगार कर्मचारियों के सम्मेलन के लिए डेलीगेट कैम्प 8 अप्रैल की शाम से शुरू होगा और यह 11 अप्रैल की दोपहर बाद तक चलेगा. सीटू के लिए डेलीगेट कैम्प 10 अप्रैल की शाम से शुरू होगा और 16 अप्रैल की सुबह बंद हो जाएगा. यदि कोई इसके बाद रहने की सुविधा चाहता है है तो उन्हें अपने प्रबंध स्वयं करने होंगे.

4. महिला-कर्मचारी डेलीगेटों के लिए 9 और 10 अप्रैल के लिए भोजन-राशि 20 रुपये होगी. उन डेलीगेटों को जो बाद में सीटू के सम्मेलन में भाग लेंगे, 50 रुपये अतिरिक्त अदायगी करनी होगी. सीटू सम्मेलनों के डेलीगेट को 11 की सुबह से 15 अप्रैल तक खाना मिलेगा और इसके लिए 50 रुपये देने होगे न कि 60 रुपये, जैसे कि गलती से पहले सरकुलर में दिया जा चुका है.

5. जो डेलीगेट कैम्प में अपने संबंधियों के साथ ठहरेंगे, यदि उन्हें कैम्प में ठहरने की अनुमति दी गई, उन्हें अपने संबंधियों के लिए भी भोजन राशि देनी होगी.

6. सीटू का केन्द्रीय कार्यालय मद्रास में 7 अप्रैल से काम करना शुरू कर देगा. सभी पत्र-व्यवहार स्वागत कमेटी के पते पर करें.

7. सभी यूनियनें सम्बद्धता-फीस की अदायगी की रसीदें या मनीआर्डर की रसीदें लाएं ताकि डेलीगेशन को स्वीकृति देने में आसानी हो.

8. सभी यूनियनें जुलूस और जन-सभा के लिए अपने झण्डे और फैस्टून आदि लाएं.

सूचना

'सीटू मजदूर' का मई अंक सीटू-सम्मेलन व मई दिवस विशेषांक होगा. 32 पृष्ठ के इस अंक की कीमत एक रुपया होगी. अपने आर्डर अभी से बुक करा लीजिए.

यूगोस्लाव यूनियन नेता से बातचीत

युगोस्लाविया की यूनियन आफ एनर्जी वर्कर्स के अध्यक्ष, कामरेड उमेनी 26 मार्च को हमारे कार्यालय में आए. कामरेड शिवाजी पटनायक, कामरेड विश्वनाथ मेनन, कामरेड नृसिंह चक्रवर्ती और कामरेड शांति शेखर बोस ने उनसे विकासशील देशों के ट्रेड यूनियन आंदोलन की भूमिका पर विचार-विमर्श किया.

जमशेदपुर में मजदूरों की लम्बी हड़ताल

हिंद टूल्स एंड डाईज इंडिया आटोमोटिव लिमिटेड, आदित्यपुर, जमशेदपुर के 400 मजदूर 15 दिसंबर 1978 से लगातार हड़ताल पर हैं. इस हड़ताल को अब तीन महीने होने को आ रहे हैं, श्रमविभाग मामला सुलझाने में असफल रहा है. सिंहभूम इंडस्ट्रियल मजदूर यूनियन (सीटू) के नेतृत्व में ये हड़ताली मजदूर गैर कानूनी तरीके से इमरजेंसी में निकाले गए अपने 20 साथियों की नौकरी की बहाली के लिए संघर्ष कर रही हैं.

यूनियन के शांतिपूर्वक तरीके से मामला तय करने की कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकला है. प्रबंधक हड़ताल तोड़ने की हर कोशिश कर रहे हैं, क्षेत्र में दंगे-फिसाद करा रहे है. उन्होंने नए आदमियों के नाम पर गुंडों को सुपरवाइजर व ट्रेनी के रूप में भर्ती कर लिया है ताकि मजदूरों पर बाकायदा हमले किए जाने में आसानी हो, अनेक मजदूरों व ट्रेड यूनियन कार्यकर्त्ताओं को झूठे मामलों में फंसा दिया गया है—हालांकि हड़ताल पूरी तरह से शांतिपूर्ण है. कई यूनियन कार्यकर्त्ताओं को धारा 307 के तहत कातिलाना हमले का दोष लगाकर फंसा दिया गया है. इसके बावजूद मजदूर एकजुट होकर संघर्ष तेज कर रहे हैं.यूनियन ने जमशेदपुर की जनता व दूसरे मजदूरों से हड़ताल को सफल बनाने के लिए सहयोग देने और नई भर्ती के नाम पर प्रबंधकों की हड़ताल तोड़ने की साजिश को नाकाम करने का आह्वान किया है.

संपादक मंडल

बी टी रणदिवे (अध्यक्ष)

पी राममूर्ति — मनोरंजन राय

निरेन घोष — सुधिन कुमार

एम के पंधे (संपादक)

एम के पंधे द्वारा सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्ज़ के लिए 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, 1, लारेंस रोड, रामपुरा, नई दिल्ली-110035 से मुद्रित (फोन 384071)